



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, ब्रीरवार, ८ मई, १९९७/१८ बैशाख, १९१९

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग  
विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

[शिमला-२, ८ मई, १९९७]

संख्या एल० एल० आर०-डी(६)-११/९७ लेजिस.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद २०० के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक ७ मई, १९९७ को अनुमोदित मन्त्रियों के वेतन और भत्ता

(हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 1997 (1997 का विधेयक संख्यांक 11) को 1997 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में, संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

सुरेन्द सिंह ठाकुर,  
सचिव (विधि)।

1997 का अधिनियम संख्यांक 13.

**मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1997**

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 1997 को यथा अनुमोदित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 (1971 का 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 1997 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 3 दिसम्बर, 1993 से प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 1971 की धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 4 का प्रतिस्थापन।

“4. मन्त्रियों के निवास स्थान.—(1) प्रत्येक मन्त्री को, एक निःशुल्क सुसज्जित गृह दिया जाएगा, जिसके अनुरक्षण का प्रभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा या ऐसे गृह के स्थान पर, निम्नलिखित दरों पर भत्ता संदत्त किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) मन्त्री जो मन्त्रिमण्डल का सदस्य है .. तीन हजार पांच सौ रुपए प्रति मास ;

(ख) राज्य मन्त्री .. तीन हजार रुपए प्रति मास ।

(2) राज्य सरकार, मन्त्री को दिए गए गृह का उसे, उसके मन्त्री न रहने की तारीख से पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए निःशुल्क अधिभोग करने की अनुज्ञा दे सकेगी ।

स्पष्टीकरण.—मन्त्री ऐसे किसी मामले में जहां उसको आवास के लिए आर्बिट्रि गृह का मानक किराया उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट रकम से अधिक हो, किसी संदाय के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।”

Act No. 13 of 1997.

# THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH) AMENDMENT ACT, 1997

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MAY, 1997)

AN

ACT

*further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971 (Act No. 3 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-eighth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title  
and com-  
mencement.

1. (1) This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 1997.

(2) It shall and shall be deemed to have come into force with effect from the 3rd day of December, 1993.

Substitution  
of section 4.

2. For section 4 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 1971, the following shall be substituted, namely :—

“4. *Residence of Minister.*—(1) Each Minister shall be provided with a free furnished house, the maintenance charges of which shall be borne by the State Government or in lieu of such house, shall be paid an allowance at the following rates, namely:—

(a) a Minister who is a member of the Cabinet.. Rupees three thousand and five hundred per mensem;

(b) a Minister of State .. Rupees three thousand per mensem.

(2) The State Government may allow a Minister to continue in free occupation of the house provided to him for a period not exceeding fifteen days from the date of his ceasing to be a Minister.

*Explanation.*—The Minister shall not become liable personally for any payment in case the standard rent of the house allotted to him for residence exceeds the amount specified in sub-section (1).”